[2025] 3 एससीआर 234: 2025 आईएनएससी 241

जयदीप बोस

बनाम

मेसर्स बिड एंड हैमर ऑक्शनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

(आपराधिक अपील संख्या 814/2025)

18 फरवरी 2025

[जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन, जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आई.पी.सी. धारा 499 एवं 500, के अंतर्गत अपराधों के लिए आरंभ की गई आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने हेतु दायर याचिका को खारिज करना विधिसम्मत एवं न्यायोचित था?

शीर्ष टिप्पणियाँ

दंड संहिता, 1860 - धारा 499, 500 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 202 - प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 - निजी शिकायत - आपराधिक मानहानि - प्रक्रिया जारी करने से पहले न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जांच - संपादक के अलावा अन्य कानूनी संस्थाओं का दायित्व - शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने सीआरपीसी की धारा 200 आरडब्ल्यू एसएस 499 और 500 आईपीसी के तहत 14 आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग तारीखों पर लिखे गए और अलग-अलग संस्करणों में प्रकाशित विभिन्न समाचार

लेखों से संबंधित एक ही शिकायत दर्ज की। विभिन्न राज्यों, जिनमें प्रतिवादी द्वारा नीलाम की जाने वाली कुछ चित्रों की प्रामाणिकता के संबंध में कथित मानहानिकारक सामग्री थी। - प्रतिवादी की जांच की गई और उसका बयान दर्ज किया गया। - इसके बाद, न्यायिक दंडाधिकारी ने शिकायत का संज्ञान लिया, इसे दर्ज करने का निर्देश दिया और अभियुक्तों को समन जारी किया - अपीलकर्ता-आरोपी और कंपनी-A1 ने उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की - उच्च न्यायालय ने केवल कंपनी A1 के संबंध में शिकायत को रद्द कर दिया, हालांकि, अपीलकर्ताओं के खिलाफ खारिज कर दिया गया - क्या यह विधिसम्मत/सही है?:

अभिनिर्धारित: यह संपादक है जो प्रकाशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेता है कि प्रकाशित सामग्री कानूनी मानकों का पालन करती है - केवल इसलिए कि अधिनियम, कंपनी के प्रकाशन में अन्य भूमिकाएं निभाने वाले व्यक्तियों का उल्लेख नहीं करता है, जैसे कि संपादकीय निदेशक, या प्रकाशन को अनिवार्य करता है, उनके नाम, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों को किसी भी मानहानिकारक सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है - मुख्य अंतर यह है कि एक संपादक के विपरीत, जिसके खिलाफ एक वैधानिक अनुमान लगाया जाता है, शुरुआत में संपादकीय निदेशक के खिलाफ ऐसी कोई धारणा नहीं है - जबकि अधिनियम किसी अन्य कानूनी इकाई को मान्यता नहीं देता है-मुख्य संपादक, प्रबंध संपादक, आदि एक अनुमान लगाने के लिए, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अभी भी कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन केवल तभी जब उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए जाते हैं - शिकायत केवल यह आरोप लगाती है कि कंपनी के अपीलकर्ता A2-संपादकीय

निदेशक, प्रकाशनों की देखरेख करते हैं, यह स्थापित करने के लिए कोई अन्य कथन नहीं किया गया है कि समाचार पत्रों के प्रकाशनों की सामग्री के चयन को नियंत्रित करने के लिए A2 कैसे जिम्मेदार था - इतना व्यापक, विशिष्ट या ठोस विवरण के बिना सामान्य या व्यापक विवरण समन जारी करने को उचित नहीं ठहरा सकता है - उससे भी अधिक, A2 मुंबई में रहता है, जो संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है - न्यायिक दंडाधिकारी को धारा 202 (1) सीआरपीसी के अनुसार शिकायत के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता थी, हालांकि, ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी, इस प्रकार, A2 के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है - अन्य अपीलकर्ताओं के संबंध में, विभिन्न अभियुक्तों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखे गए सभी समाचार लेखों पर विचार नहीं किया गया - उच्च न्यायालय ने ए4 द्वारा लिखित केवल एक लेख का उल्लेख किया - धारा 202 सीआरपीसी के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया - न्यायिक दंडाधिकारी का आदेश प्रक्रियात्मक अनियमितता से ग्रस्त है - यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि नीलामी असफल रही थी या कोई नुकसान या हानि वास्तव में हुई थी, समाचार पत्रों में प्रकाशित कथित समाचार लेखों के कारण - इसके अलावा शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को बदनाम करने या नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है - इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा तलब आदेश और अपीलकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। [पैरा 19-20, 22]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 19(1)(a) - भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार - मीडिया की शक्ति - जनमत पर प्रभाव:

अभिनिर्धारित: अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है - मीडिया में काम करने वालों, विशेष रूप से, प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्तियों, लेखकों, आदि को किसी भी बयान, समाचार या राय को प्रकाशित करने से पहले अत्यधिक सावधानी और जिम्मेदारी बरतनी चाहिए - जनमत को आकार देने में मीडिया की शक्ति महत्वपूर्ण है और प्रेस के पास जनता की भावनाओं को प्रभावित करने और धारणाओं को बदलने की क्षमता है, उल्लेखनीय गति के साथ - इसकी विशाल पहुंच को देखते हुए, इसमें क्षमता है संबंधित लोगों की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम दूरगामी और स्थायी हो सकते हैं - मीडिया रिपोर्टिंग में सटीकता और निष्पक्षता की आवश्यकता, व्यक्तियों या संस्थानों की अखंडता को प्रभावित करने की क्षमता - इसके मद्देनजर, समाचार लेखों का प्रकाशन जनहित में और अच्छे विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। [पैरा 21]

उद्घृत निर्णयजन्य विधि

अरून पुरी बनाम दिल्ली राज्य **[2022] 18 एससीआर 311: 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1491**; इवेको मैगिरस ब्रांड्सचुट्ज़टेक्निक जीएमबीएच बनाम निर्मल किशोर भारतीय **[2023] 13 एससीआर 220: (2024)** 2 एससीसी 86; ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड [2024] 3 एससीआर 994: 2024 आईएनएससी 255; पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम

विशेष न्यायिक न्यायिक दंडाधिकारी और अन्य [1997] सप्प 5 एससीआर 12: (1998) 5 एससीसी 749; अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुकर निंबालकर [2016] 9 एससीआर 475: (2017) 3 एससीसी 528; केएम मैथ्यू बनाम केए अब्राहम [2002] सप्लीमेंट 1 एससीआर 662: 2002 (6) एससीसी 670; गंभीर सिंह आर. डेकरे बनाम फाल्गुनभाई चिमनभाई पटेल [2013] 4 एससीआर 719: (2013) 3 एससीसी 697 - संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867; दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (2005 का केंद्रीय अधिनियम 25)।

प्रमुख शब्दों की सूची

आपराधिक मानहानि; चित्रों की प्रामाणिकता; समाचार लेख; चित्रों की नीलामी; न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जांच; संपादकीय निदेशक; अपमानजनक समाचार लेख; प्रकाशन में पारदर्शिता; निजी शिकायत; बदनाम करने का इरादा; संपादक के खिलाफ वैधानिक धारणा; शिकायतों को रद्द करना; व्यक्तियों की अखंडता; मीडिया की शक्ति; जनता की राय को आकार देना; भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार; मीडिया रिपोर्टिंग में निष्पक्षता; प्रक्रिया जारी करने का स्थगन; प्रक्रिया जारी करने से पहले न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जांच; एकल शिकायत; (क) क्या यह सच है कि कुछ चित्रों की प्रामाणिकता के संबंध में मानहानिकारक सामग्री की नीलामी की जाएगी; सम्मन जारी करना; कानूनी मानक; मानहानिकारक सामग्री;

संपादकीय निदेशक के खिलाफ अनुमान; न्यायिक दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र के बाहर; प्रक्रियात्मक अनियमितता; समाचार लेखों का प्रकाशन।

मामले की उत्पत्ति

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 814/2025

बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 18.06.2024 के निर्णय और आदेश से सीआरएलपी संख्या 3829/2017

साथ में

2025 की आपराधिक अपील संख्या 815, 816, 817

अधिवक्तागण

अपीलकर्ता की ओर से सुश्री अरुंधति काटजू, **वरिष्ठ** अधिवक्ता, ऐश्वर्या कौशिक, प्रशांत एमएस, रवि भरुका, रोहित अग्रवाल, सुश्री सृष्टि बोरठाकुर, योगिंदर हांडू, अश्विन कटारिया, अधिवक्ता शामिल थे।

पाई अमित, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, सुश्री करिश्मा नागनूर, निखिल पाहवा, कुशल दुबे, अभियुदय वत्स, तथागत दत्ता, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>आदेश</u>

आर. महादेवन, जे.

1. अनुमति प्रदान कि गई।

2. ये अपीलें कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बेंगलुरु में आपराधिक याचिका संख्या 3829/2017 में पारित दिनांक 18.06.2024 के एक आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसका शीर्षक 'बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम मेसर्स बिड एंड हैमर ऑक्शनियर्स प्राइवेट लिमिटेड' है, जो पीसीआर संख्या 13146/2014 और सीसी संख्या 18491/2016 में शिकायत से उत्पन्न हुआ है, जो द्वितीय अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत की फाइल पर लंबित है। बेंगलुरु। उक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 और 500 के तहत अपराधों के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी गई थी, हालांकि, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 और 500 के तहत अपराधों के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी गई थी, हालांकि, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 और 500 के तहत अपराधों को रद्द कर दिया गया। जहां तक मैसर्स बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड4 का संबंध है। (आरोपी नंबर 1) का संबंध है।

3. वर्तमान मामलों की उत्पत्ति शिकायतकर्ता/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 22.08.2014 को दायर एक निजी शिकायत में निहित है, जिसमें कंपनी और उसके निदेशकों, संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता,

19735 की धारा 200 के साथ पठित धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत 14 आरोपी व्यक्ति शामिल हैं। शिकायत की गंभीरता विभिन्न समाचार पत्रों जैसे बैंगलोर मिरर, मुंबई मिरर, द टाइम्स ऑफ इंडिया (बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और पुणे संस्करण) और द इकोनॉमिक टाइम्स (नई दिल्ली और मुंबई संस्करण) में 27.06.2014, 28.06.2014, 29.06.2014, 06.07.2014, 07.07.2014 और 20.07.2014 को प्रकाशित कुछ समाचार लेखों से संबंधित है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा नीलाम किए जाने वाले कुछ चित्रों की प्रामाणिकता के संबंध में कथित मानहानिकारक सामग्री शामिल थी।

4. शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी का शपथ बयान 14.11.2014 को दर्ज किया गया था। इसके बाद, विचारण न्यायालय ने शिकायत का संज्ञान लिया और आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराधों के लिए इसे दर्ज करने और दिनांक 29.07.2016 के आदेश के माध्यम से आरोपी को समन जारी करने का निर्देश दिया। शिकायत पीसीआर संख्या 13146/2014 के रूप में प्राप्त हुई थी और बाद में, सीसी संख्या 18491/2016 के रूप में पंजीकृत की गई थी, जो अब विचारण न्यायालय की फाइल पर लंबित है।

5. समन जारी करने को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की आपराधिक याचिका संख्या 3829 दायर की, जिसमें उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई। विधिवत प्रतिवाद (सुनवाई) के बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया, हालांकि, जहां

तक कंपनी (A1) का संबंध है, शिकायत को रद्द कर दिया। उसी से व्यथित होकर, अपीलकर्ता वर्तमान अपीलों के साथ हमारे सामने हैं।

<u>पक्षकारों की दलीलें</u>

6. अपीलकर्ता/आरोपी नंबर 2 [एसएलपी (सीआरएल) संख्या 10212 ऑफ 2024] के विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

(a) अपीलकर्ता न तो कथित मानहानिकारक समाचार लेखों का लेखक है और न ही किसी भी समाचार पत्र का संपादक है; और वह कंपनी के संपादकीय निदेशक हैं; और इसलिए, वह कथित अपमानजनक समाचार लेखों के प्रकाशन के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

(b) प्रतिवादी **द्वारा** दायर निजी शिकायत में, कथित मानहानिकारक समाचार लेखों को प्रकाशित करने में अपीलकर्ता की भूमिका के बारे में कोई विशिष्ट कथन नहीं है, सिवाय इसके कि कंपनी के संपादकीय निदेशक के रूप में उसका नाम उल्लेख किया गया है और इस प्रकार, उसे आरोपी के रूप में पेश नहीं किया जा सकता था।

(c) प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के तहत, यह "संपादक" है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित सामग्री के चयन को नियंत्रित करता है, इसके अलावा संपादक, मुद्रक और प्रकाशक के नाम समाचार पत्रों की प्रिंट लाइन में प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। अपीलकर्ता का नाम किसी भी समाचार पत्र

की प्रिंट लाइन में दिखाई नहीं देता है जिसने प्रश्न में समाचार लेख प्रकाशित किए थे। आक्षेपित समाचार लेखों के प्रकाशन में अपीलकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी के बारे में किसी विशेष आरोप के बिना "संपादकीय निदेशक" का पदनाम, आपराधिक दायित्व का आधार नहीं बन सकता है। इसलिए, अपीलकर्ता को कथित अपराधों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

(d) आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 202, जिसे वर्ष 2005 में संशोधित किया गया, यह अनिवार्य करती है कि न्यायिक दंडाधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर निवास करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व जांच की जाए। इस प्रावधान का उद्देश्य दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों को झूठी शिकायतों के माध्यम से उत्पीड़न से बचाना है।वर्तमान मामले में, न्यायिक दंडाधिकारी ने परिवादी (शिकायतकर्ता) के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी का परीक्षण नहीं किया, और परिवादी का कथन स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के विरुद्ध मानहानि के आरोप को सिद्ध करने में असफल रहता है।अतः अपीलकर्ता, जो कि मुंबई में निवास करता है अर्थात बेंगलुरु न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने से पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अनिवार्य प्रावधान का पालन न किया जाना, उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई आपराधिक कार्यवाही को अवैध कर देता है।

(e) शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत आपराधिक मानहानि के आवश्यक तत्वों का अभाव है। उक्त धारा के स्पष्टीकरण के लिए स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि आरोपण को दूसरों के आकलन में किसी व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम करना चाहिए। जबकि, प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत पूरी तरह से शिकायतकर्ता के नुकसान के आत्म-अनुमान पर निर्भर करती है, बिना किसी तीसरे पक्ष से प्रतिष्ठा के नुकसान के बारे में कोई सबूत नहीं। इस प्रकार दूसरों की नजर में प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने में विफलता, उक्त शिकायत विधिसम्मत नहीं है।

(f) इन सभी पहलुओं की ठीक से सराहना किए बिना, केवल इस धारणा पर कि अपीलकर्ता संपादकीय निदेशक है, सभी समाचार पत्रों की सामग्री की देखरेख कर रहा है और कथित मानहानिकारक समाचार लेखों के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक याचिका को यहां दिए गए आदेश द्वारा खारिज कर दिया, जिसे इस न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना है।

7. अपीलकर्ता/आरोपी नंबर 12 [एसएलपी (सीआरएल) संख्या 13443/2024] के विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं

(a) यहाँ विवादित आदेश में केवल दिनांक 27.06.2014 को प्रकाशित उस लेख का उल्लेख किया गया है, जिसका शीर्षक “Fakes at Art Auction Raise Huge Storm” है, जो नीलामी के दिन

प्रकाशित हुआ था और जिसे सुश्री नीलम राज (आरोपी क्रमांक-4) **द्वारा** लिखा गया था; जबकि अपीलकर्ता द्वारा लिखित लेख का उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

(b) ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ता ने उक्त लेख में योगदान दिया या सहायता की या शामिल था। यहां तक कि शिकायत में भी केवल एक ही आरोप है कि सभी आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर एक बदनामी अभियान चलाया है जिसका उद्देश्य शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना है और समाचार लेखों को नीलामी की तारीख पर प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रकार, साजिश के आरोप को साबित करने के लिए एक गंजा बयान है।

(c) अपीलकर्ता ने 'कला की पहचान का संकट' ‘Art’s Identity Crisis’,शीर्षक से एक पूरी तरह से अलग लेख लिखा, जो 20.07.2014 को प्रकाशित हुआ था, यानी 27.06.2014 की नीलामी के लगभग एक महीने बाद। उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा नीलाम किए जा रहे चित्रों की प्रामाणिकता के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, बल्कि उक्त लेख भारतीय कला को प्रमाणित करने की चुनौती पर केंद्रित था और यह कैसे विज्ञान पर कम और भारत में एक कलाकार के परिवार पर अधिक निर्भर करता है। इसलिए, अपीलकर्ता का लेख मानहानिकारक नहीं था और आईपीसी की धारा 499/500 के तहत अपराध का गठन नहीं करता था।

(d) अरून पुरी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य 6 और इवेको मैगिरस में इस न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया गया था। ब्रांड्सचुट्ज़टेक्निक जीएमबीएच बनाम निर्मल किशोर भारतीय, 7 के मामले में , यह माना गया था कि इस बात पर कोई रोक नहीं है कि आईपीसी की धारा 499 के अपवादों को केवल मुकदमे के चरण में ही माना जा सकता है।

(e) तथापि, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 4 द्वारा लिखित लेख के आधार पर और अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से लिखे गए लेख पर न्यायिक सोच का प्रयोग किए बिना, न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष शिकायत और उससे उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही को बरकरार रखने में गलती की।

(f) शिकायतकर्ता को छोड़कर न्यायिक दंडाधिकारी ने किसी अन्य गवाह से पूछताछ नहीं की। अपीलकर्ता मुंबई में रहता है, यानी न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर, लेकिन समन जारी करने से पहले कोई जांच नहीं की गई थी, "अतः, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत अनिवार्य प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन नहीं किया गया। फलस्वरूप, समन आदेश विधि-विरुद्ध (कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण) था।"

(g) किसी अन्य कथित रूप से मानहानिकारक लेख का तथ्यात्मक संदर्भ या किसी पत्रकार द्वारा तीसरे पक्ष के विचार को दर्ज करने को मानहानिकारक नहीं माना जा सकता है और ऐसा करने से

प्रेस की स्वतंत्रता गंभीर रूप से प्रभावित होगी और अपीलकर्ता को उसके खिलाफ गलत तरीके से लागू किए जा रहे देश के कानून का शिकार होने और न्याय का घोर उल्लंघन" होने के खतरे में डाल दिया जाएगा।

(h) यह आरोप लगाया जाता है कि शिकायतकर्ता एक धारावाहिक वादी प्रतीत होता है जो प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं वाक्-स्वतंत्रता को दबाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया का सहारा ले रहा है, जब कला विशेषज्ञों ने शिकायतकर्ता द्वारा इसकी नीलामी में बेचे जा रहे चित्रों की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया था।

(i) *ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड8* के मामले में इस न्यायालय ने माना है कि पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की रक्षा के संवैधानिक जनादेश को कम करके नहीं आंका जा सकता है।

(j) प्रतिवादी द्वारा दायर इसी तरह की मानहानि की शिकायत को इस न्यायालय द्वारा एसएलपी (सीआरएल) से उत्पन्न होने वाली 2022 की आपराधिक अपील संख्या 1008 में पारित दिनांक 20.07.2022 के फैसले के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। *मैसर्स डीएजी प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिड एंड हैमर नीलामीकर्ता (प्रा) लिमिटेड* शीर्षक से संख्या 6732/2019 इन प्रस्तुतियों के साथ, विद्वान वकील ने अपील की अनुमति देने और इस

अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया।

8. अपीलकर्ताओं/आरोपी संख्या 8, 9, 10 और 13 [एसएलपी (सीआरएल) संख्या 15653 ऑफ 2024] के विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

(a) विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा लिखे गए समाचार लेखों की अनदेखी की और केवल शिकायत में दिए गए समाचार लेखों की प्रतिवादी द्वारा की गई व्याख्या और उसके शपथ ग्रहण वक्तव्य के आधार पर जारी करने की प्रक्रिया में गलती की। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित आदेश में केवल सुश्री नीलम राज (आरोपी नंबर 4) द्वारा लिखे गए लेख का उल्लेख किया और अपीलकर्ताओं द्वारा लिखे गए समाचार लेखों पर विचार नहीं किया कि क्या वे मानहानिकारक थे या नहीं।

(b) प्रतिवादी ने शिकायत के पैराग्राफ 16 में कहा कि आरोपी नंबर 5-मौलिक व्यास और अपीलकर्ता नंबर 4 (आरोपी नंबर 13) ने इकोनॉमिक टाइम्स में दिनांक 27.06.2014 के लेख का सह-लेखन किया था, हालांकि, उक्त लेख के अवलोकन से पता चलता है कि यह आरोपी नंबर 5-मौलिक व्यास द्वारा लिखा गया है और कहा जाता है कि केवल इनपुट आरोपी नंबर 13 द्वारा दिए गए थे। यह लेख केवल कानूनी नोटिसों के आदान-प्रदान के बारे में

जानकारी प्रदान करता है और प्रतिवादी के वकील की टिप्पणियों का उल्लेख करता है।

(c) चूंकि सभी अपीलकर्ताओं के कार्यालय मुंबई और कोलकाता में हैं, यानी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर, न्यायिक दंडाधिकारी को प्रक्रिया जारी करने से पहले शिकायतकर्ता के अलावा अन्य गवाहों की जांच करके आवश्यक धारा 202 सीआरपीसी के तहत जांच करनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया था।

(d) *पेप्सी फूड्स लि और अन्य बनाम पेप्सी फूड्स लिमिटेड* के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका को रेखांकित करने के संबंध में समन आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है। विशेष न्यायिक न्यायिक दंडाधिकारी और अन्य।

(e) प्रतिवादी ने कोई कानूनी सबूत पेश नहीं किया और उसका बयान अपीलकर्ताओं के खिलाफ मानहानि के आरोप को साबित करने में स्पष्ट रूप से विफल रहा।

(f) शिकायत मूल रूप से त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि आत्म-आकलन मानहानि नहीं होता है। चूँकि कोई भी गवाह यह कहने के लिए आगे नहीं आया कि शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा उसकी दृष्टि में कम हुई है, और न ही कोई तृतीय व्यक्ति न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ जिसने प्रथमदृष्टया यह दावा किया हो कि प्रतिवादी की प्रतिष्ठा उनकी दृष्टि में घटी है।

ऐसा कहते हुए, विद्वान वकील ने प्रतिवादी द्वारा दायर निजी शिकायत के आधार पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।

9. अपीलकर्ता/आरोपी नंबर 4 [एसएलपी (सीआरएल) संख्या 16153/2024] के विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

(a) अपीलकर्ता ने दो समाचार लेख लिखे, जिन्हें डेस्क द्वारा तय किए गए अनुसार अलग-अलग शीर्षकों का उपयोग करते हुए अलग-अलग संस्करणों में प्रकाशित किया गया था। यह कहा गया था कि किसी लेख के कुछ हिस्सों को उस संस्करण के संपादक के विवेक के अनुसार हटा दिया जाता है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में केवल एक लेख पर चर्चा की गई और अपीलकर्ता के दूसरे लेख पर पूरी तरह से चुप रहा और इसलिए, इसे रद्द किया जा सकता है।

(b) समाचार लेखों में केवल यह कहा गया है कि विशेषज्ञों ने प्रतिवादी के विरुद्ध धारणा/निष्कर्ष निकाले बिना प्रश्न उठाए हैं और इसलिए इसे मानहानि का अपराध नहीं माना जाएगा।

(c) इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस में पहले से प्रकाशित एक लेख को आगे बढ़ाने के लिए समाचार लेख प्रकाशित किए गए थे, जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में था, और बाद में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर समींद्रनाथ मजूमदार द्वारा शुरू की गई बहस के रूप में।

(d) प्रकाशित लेख में विभिन्न कला विशेषज्ञों और कलाकारों के परिवार के सदस्यों जैसे रुखसाना पठान आरा, सुशोभन अधिकारी, प्रो आर शिवकुमार, बालक भट्टाचार्जी, आशीष आनंद, रजनी प्रसन्ना हेब्बार के वक्तव्य उद्धृत किए गए हैं; और अपीलकर्ता द्वारा कला के किसी भी कार्य पर कोई निर्णय नहीं दिया गया था। हालांकि, विचारण न्यायालय ने प्रकाशन की पूरी सामग्री को देखे बिना, शिकायत में समाचार लेखों की प्रतिवादी की व्याख्या और उसके शपथ बयान के आधार पर प्रक्रिया जारी की।

(e) प्रतिवादी ने कोई कानूनी साक्ष्य पेश नहीं किया और शिकायतकर्ता के बयान भी मानहानि के आरोप को साबित करने में स्पष्ट रूप से विफल रहे। इसके अलावा, समन आदेश मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण था क्योंकि कोई भी तीसरा व्यक्ति न्यायिक दंडाधिकारी के सामने नहीं आया था ताकि प्रथम दृष्टया यह कहा जा सके कि प्रतिवादी की प्रतिष्ठा उनके अनुमान में कम हो गई थी। इस सामग्री के अभाव में, समन आदेश कानून में खराब है।

(f) इन सभी पहलुओं पर विचार किए बिना, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा आपराधिक याचिका को खारिज करने में त्रुटि की है। उक्त आदेश गंभीर एवं स्पष्ट खामियों से ग्रस्त है तथा इसलिए निरस्त किए जाने योग्य है।

10. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता को एक समृद्ध विरासत प्राप्त है जो त्रुटिहीन चरित्र और प्रतिष्ठा के व्यक्तियों द्वारा शामिल किए जाने के

कारण ईर्ष्यापूर्ण है। इसके विपरीत, मानहानिकारक समाचार लेखों का शिकायतकर्ता कंपनी की प्रतिष्ठा पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। समाचार लेख व्यापक रूप से प्रसारित किए गए और कंपनी के व्यावसायिक हितों को काफी नुकसान पहुंचाया। परिणामस्वरूप, कंपनी की प्रतिष्ठा काफी धूमिल हो गई है, और इसके ग्राहकों, भागीदारों और जनता की नज़र में इसकी विश्वसनीयता कम हो गई है। प्रतिष्ठा को हुए पर्याप्त नुकसान के आलोक में, प्रतिवादी ने मानहानि करने के लिए आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत को प्राथमिकता दी। न्यायिक दंडाधिकारी ने संबंधित समाचार लेखों की मानहानिकारक प्रकृति पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, शिकायत दर्ज करने और आरोपी को समन जारी करने का निर्देश दिया।

10.1 विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि शिकायत स्वयं समाचार पत्रों में मानहानिकारक समाचार लेखों के प्रकाशन में अपीलकर्ताओं की भूमिका को स्थापित करती है। शिकायतकर्ता ने समाचार लेखों की मानहानिकारक प्रकृति को पर्याप्त रूप से रेखांकित किया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। विचारण न्यायालय द्वारा समन जारी करना संज्ञान और प्रक्रिया जारी करने के चरण को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप है, जहां मामले के गुण-दोष की विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय की टिप्पणियां, जिनमें आक्षेपित आदेश अनुच्छेद 3 में दी गई टिप्पणियां भी शामिल हैं, तथ्यों की प्रथम दृष्टया सराहना पर आधारित हैं और मामले पर पूर्वाग्रह नहीं डालती हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सम्मन के

चरण, शिकायतकर्ता को संदेह से परे अपने मामले को साबित करने की आवश्यकता नहीं है; प्रथम दृष्टया एक मात्र मामला पर्याप्त है। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय ने समन को चुनौती देने को सही ढंग से खारिज कर दिया और इस अदालत द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

11. हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का भी अवलोकन किया।

12. 2024 की एसएलपी (आपराधिक) संख्या 10212 में दिनांक 12.08.202410 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने अगले आदेश तक शिकायत मामला संख्या 18491/2016 के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। इसी तरह का आदेश इस न्यायालय द्वारा 14.10.2024 को एसएलपी (आपराधिक) संख्या 13443 में भी पारित किया गया था। नतीजतन, 2024 की एसएलपी (आपराधिक) संख्या 15653 में अपीलकर्ता और 2024 के एसएलपी (आपराधिक) संख्या 16153 में अपीलकर्ताओं को क्रमशः 11.11.2024 और 14.11.2024 के आदेशों के माध्यम से ऐसा लाभ भी दिया गया था।

<u>कानूनी प्रावधान</u>

13. शुरुआत में, हम लागू प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हैं वर्तमान मामला, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(a) प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867

<u>धारा 1 - निर्वचन खण्ड</u>

*-**संपादक'** का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले मामले के चयन को नियंत्रित करता है।*

*'**समाचार पत्र**' का अर्थ है कोई भी मुद्रित आवधिक कार्य जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियां होती हैं*

<u>धारा 5</u>

***समाचार पत्रों के प्रकाशन के* नियम** । *भारत में कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं किया जाएगा, इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुरूप होने के अलावा:*

(1) धारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे प्रत्येक समाचार पत्र की प्रत्येक प्रति में ऐसी प्रति पर स्पष्ट रूप से मुद्रित स्वामी और उसके संपादक के नाम और उसके प्रकाशन की तारीख भी अंकित होगी। (2) ....."

<u>धारा 7</u>

*पीठ ने कहा, **"घोषणा की कार्यालय प्रति प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी**। किसी भी कानूनी कार्यवाही में, साथ ही सिविल और आपराधिक भी, ऐसी घोषणा की एक प्रति का उत्पादन, जैसा कि पूर्वोक्त है, इस अधिनियम द्वारा सशक्त किसी न्यायालय*

की मुहर द्वारा सत्यापित किया गया है, ऐसी घोषणाओं की अभिरक्षा के लिए, या, संपादक के मामले में, संपादक के रूप में उसके नाम के साथ छपी समाचार पत्र की एक प्रति (जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए) पर्याप्त सबूत माना जाएगा, उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसका नाम ऐसी घोषणा के लिए अभिलिखित किया जाएगा, या ऐसे समाचार पत्र पर मुद्रित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, कि उक्त व्यक्ति प्रत्येक समाचार पत्र के प्रत्येक भाग का मुद्रक या प्रकाशक, या मुद्रक और प्रकाशक (जैसा कि उक्त घोषणा के शब्दों के अनुसार हो सकता है) था, जिसका शीर्षक घोषणा में उल्लिखित समाचार पत्र के शीर्षक के अनुरूप होगा, या अखबार के उस अंक के हर हिस्से का संपादक जिसकी एक प्रति तैयार की जाती है।

13.1 उपर्युक्त उपबंधों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक समाचार पत्र को अपने स्वामी और संपादक के नामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए, जिससे प्रकाशन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, संपादक पर एक वैधानिक अनुमान लगाया जाता है, जो बाद में प्रकाशित होने वाली सामग्री के चयन के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे वह उसी के लिए जवाबदेह हो जाता है जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।

(b) भारतीय दंड संहिता, 1860

<u>धारा 499</u>

मानहानि *- जो को, शब्दों से या तो बोले गए या इरादे से पढ़ा जाना, या संकेतों द्वारा या दृश्यमान अभ्यावेदन द्वारा, किसी भी व्यक्ति के संबंध में कोई आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है जो नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है, या यह जानने या विश्वास करने का कारण है कि इस तरह के आरोप से नुकसान होगा, ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इसके बाद अपेक्षित मामलों को छोड़कर, उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए कहा जाता है।*

स्पष्टीकरण 1*.– यह एक मृत व्यक्ति को कुछ भी आरोपित करने के लिए मानहानि के बराबर हो सकता है, यदि आरोप उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है यदि वह जीवित है, और इसका उद्देश्य उसके परिवार या अन्य निकट रिश्तेदारों की भावनाओं को आहत करना है।*

स्पष्टीकरण 2.*– किसी कंपनी या संघ या व्यक्तियों के संग्रह के संबंध में आरोप लगाना मानहानि के बराबर हो सकता है।*

स्पष्टीकरण 3*.– एक विकल्प के रूप में एक आरोप, या विडंबना के रूप में व्यक्त किया गया, मानहानि के बराबर हो सकता है।*

स्पष्टीकरण 4*.– किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई आरोप नहीं कहा जाता है, जब तक कि वह आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरों के आकलन में, उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता है, या उस*

व्यक्ति के चरित्र को उसकी जाति या उसकी बुलाहट के संबंध में कम नहीं करता है, या उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम नहीं करता है, या यह विश्वास नहीं करता है कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित स्थिति में है, या आम तौर पर अपमानजनक माने जाने वाले राज्य में।

धारा 500

मानहानि की सजा *- जो कोई दूसरे को बदनाम करता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।*

13.2. उपरोक्त प्रावधानों से, यह स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि के लिए नुकसान पहुंचाने या यह ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है कि आरोप से नुकसान होने की संभावना है, और यह कि आरोप दूसरों के अनुमान में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मानहानि का सार केवल एक आरोप लगाने में नहीं है, बल्कि जनता की धारणा पर इसके प्रभाव में है, जिससे समाज में व्यक्ति की स्थिति प्रभावित होती है।

(c) आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

धारा 202

प्रक्रिया जारी करने का स्थगन।

(1) *कोई न्यायिक दंडाधिकारी , किसी ऐसे अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, जिसका वह संज्ञान लेने के लिए प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसे सौंपा गया है,* ***यदि वह ठीक समझे, [और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है]*** *[2005 के अधिनियम 25 द्वारा डाला गया, धारा 19 (23-6-2006 से प्रभावी).] अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित कर दे, और या तो स्वयं मामले की जांच कर या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश दे सके, जो वह उचित समझे, यह निर्णय करने के प्रयोजन के लिए कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं:*

बशर्ते कि जांच के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा, -

(a) जहां न्यायिक दंडाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि जिस अपराध की शिकायत की गई है वह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है; या

(b) जहां किसी न्यायालय द्वारा शिकायत नहीं की गई है, जब तक कि शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों (यदि कोई हो) की धारा 200 के तहत शपथ पर जांच नहीं की गई हो।

(2) उप-धारा (1) के तहत एक जांच में, न्यायिक दंडाधिकारी , यदि वह उचित समझता है, तो शपथ पर गवाहों के साक्ष्य ले सकता है:

बशर्ते कि यदि न्यायिक दंडाधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि जिस अपराध की शिकायत की गई है वह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाहों को पेश करने और शपथ पर उनकी जांच करने के लिए कहेगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी न है, तो उसके पास उस अन्वेषण के लिए किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी, सिवाय बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति।

13.3 उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत प्राप्त होने पर, न्यायिक दंडाधिकारी को आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए आगे बढ़ने से पहले अनिवार्य रूप से जांच या जांच करनी चाहिए, यदि ऐसा आरोपी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है। दूसरे शब्दों में, न्यायिक दंडाधिकारी को उन मामलों में समन जारी करने से पहले गवाहों की जांच करनी चाहिए जहां आरोपी न्यायिक दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है। जांच या अन्वेषण की यह अनिवार्य आवश्यकता दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (2005 का केंद्रीय

अधिनियम 25) की धारा 19 के माध्यम से शुरू की गई थी, जो 23.06.2006 से लागू हुई थी, जिसमें 'और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है'।

13.4 उपरोक्त आवश्यकता को इस न्यायालय द्वारा *अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुकर निंबालकर*11के मामले में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं:

> **"23.** ***कानून में स्वीकृत स्थिति यह है कि उन मामलों में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, प्रक्रिया जारी करने से पहले न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से जांच या जांच करना अनिवार्य है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा वर्ष 2005 में धारा 202 में संशोधन किया गया था, जो 22-6-2006 से प्रभावी था, जिसमें "और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है"। इस संशोधन के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या उद्देश्य है, अर्थात् दूर-दराज के स्थानों पर रहने वाले ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ झूठी शिकायतों को दूर करना ताकि उन्हें अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया जा सके। इस प्रकार, संशोधित प्रावधान न्यायिक दंडाधिकारी पर जांच करने या निर्देश देने का दायित्व डालता है।***

24. *इस संशोधन के सार और उद्देश्य को इस न्यायालय द्वारा विजय धानुका बनाम नजिमा ममताज [विजय धानुका बनाम नजिमा ममताज, (2014) 14 एससीसी 638: (2015) 1 एससीसी (सीआरआई) 479] में निम्नलिखित शब्दों में कब्जा कर लिया गया है: (एससीसी पी. 644, पैरा 11-12)*

*"11. संहिता की धारा 202, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करने पर विचार करती है 'ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है' और उसके बाद या तो स्वयं मामले की जांच करने या पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश देने के लिए जो वह उचित समझता है। इसके सामने, हमारे दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है कि क्या ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जहां **न्यायिक दंडाधिकारी** अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, जांच अनिवार्य है या नहीं।*

12. शब्द 'और करेगा, एक मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे एक स्थान पर रह रहा है जिसमें वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है' दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (2005 का केंद्रीय अधिनियम 25) की धारा 19 द्वारा 23-6-2006 से प्रभावी थे। विधायिका की राय में, उपरोक्त संशोधन आवश्यक था क्योंकि उन्हें परेशान करने के

लिए दूर-दराज के स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज की जाती हैं। संशोधन के लिए नोट इस प्रकार है:

उन्होंने कहा, 'दूर-दराज के स्थानों पर रहने वाले लोगों को परेशान करने के लिए उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज की जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेईमान व्यक्तियों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को परेशान न किया जाए, यह खंड धारा 202 की उप-धारा (1) में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि इसे अनिवार्य बनाया जा सके

न्यायिक दंडाधिकारी *को यह कहते हुए कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले अभियुक्त को बुलाने से पहले वह स्वयं मामले की जांच करेगा या किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश देगा जो वह उचित समझे, यह पता लगाने के लिए कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार था या नहीं।*

अभिव्यक्ति "करेगा" प्रथम दृष्टया जांच या न्यायिक निरीक्षण, जैसा भी मामला हो, ***न्यायिक दंडाधिकारी*** *द्वारा अनिवार्य बनाता है। शब्द "करेगा" आमतौर पर अनिवार्य है, लेकिन कभी-कभी, संदर्भ या इरादे को ध्यान में रखते हुए, इसे निर्देशिका माना जा सकता है। सभी परिस्थितियों में "करेगा" शब्द का उपयोग निर्णायक नहीं है। उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जब हम विधायिका के इरादे को देखते हैं,*

तो हम पाते हैं कि इसका उद्देश्य निर्दोष व्यक्तियों को झूठी शिकायतों से बेईमान व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न से रोकना है। इसलिए, हमारी राय में, "करेगा" अभिव्यक्ति का उपयोग और पृष्ठभूमि और जिस उद्देश्य के लिए संशोधन लाया गया है, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि ***न्यायिक दंडाधिकारी*** *के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे रहने वाले अभियुक्त के खिलाफ समन जारी करने से पहले जांच या जांच, जैसा भी मामला हो, अनिवार्य है।*

26. ***इसलिए, प्रक्रिया जारी करने से पहले जांच करने या जांच का निर्देश देने की आवश्यकता एक खाली औपचारिकता नहीं है।*** *इस प्रावधान के तहत किस तरह की "जांच" की आवश्यकता है, यह विजय धानुका मामले में भी समझाया गया है [विजय धानुका बनाम नजिमा ममताज, (2014) 14 एससीसी 638: (2015) 1 एससीसी (सीआरआई) 479], जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: (एससीसी पी. 645, पैरा 14)*

"14. *उपरोक्त प्रश्न के हमारे उत्तर को ध्यान में रखते हुए, अगला प्रश्न जो हमारे निर्धारण के लिए आता है, वह यह है कि क्या समन जारी करने से पहले विद्वान* ***न्यायिक दंडाधिकारी*** *ने जांच को अनिवार्य रूप से आयोजित किया है*

संहिता की धारा 202। "पूछताछ" शब्द को संहिता की धारा 2 (जी) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

*'2. (छ) **"जांच"** का अर्थ है एक न्यायिक दंडाधिकारी या अदालत द्वारा इस संहिता के तहत किए गए परीक्षण के अलावा हर जांच;*

उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि न्यायिक दंडाधिकारी या अदालत द्वारा किए गए मुकदमे के अलावा हर जांच एक जांच है। संहिता की धारा 202 के तहत जांच का कोई विशिष्ट तरीका या तरीका प्रदान नहीं किया गया है। संहिता की धारा 202 के तहत परिकल्पित जांच में, गवाहों की जांच की जाती है, जबकि संहिता की धारा 200 के तहत, शिकायतकर्ता की जांच केवल उपस्थित गवाहों की जांच करने के विकल्प के साथ आवश्यक है, यदि कोई हो। न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा यह कवायद, यह तय करने के उद्देश्य से कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, संहिता की धारा 202 के तहत परिकल्पित जांच के अलावा और कुछ नहीं है।

27. जब हम सम्मन आदेश का अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह ऐसी किसी भी जांच को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, आदेश में उल्लेख किया गया है कि विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने शिकायत, शिकायतकर्ता के सत्यापन बयान को पढ़ने और अभिलेख पर दायर दस्तावेजों की प्रतियों यानी शिकायत का प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुवाद, वकील के हलफनामे को पढ़ने के बाद इसे पारित किया था,

जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, आदि।

28. जहां तक इन दो आरोपी व्यक्तियों का संबंध है, सीआरपीसी की धारा 202 में उल्लिखित प्रकृति की कोई जांच नहीं की गई है।

29. विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने प्रेस अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच नहीं की और अपने दिमाग को लागू किया कि क्या कोई घोषणा है

उक्त अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों व्यक्तियों के साथ और यदि नहीं, तो संपादकों के साथ किस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस पहलू पर ध्यान देना आवश्यक था। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह न्यायालय यह सुझाव नहीं दे रहा है कि इन दो अभियुक्त व्यक्तियों के साथ केवल प्रेस अधिनियम के तहत घोषणा में उनके नाम न होने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रेस अधिनियम की धारा 7 के तहत इन व्यक्तियों के खिलाफ कोई अनुमान नहीं है और वे संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण, न्यायिक दंडाधिकारी को A-1 और A-2 के तहत समन आदेश पारित करते समय इन पहलुओं पर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता थी।

चर्चा और निष्कर्ष

14 हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी ने अलग-अलग तारीखों पर लिखे गए अलग-अलग समाचार लेखों के लिए 14 अभियुक्तों के खिलाफ एक ही शिकायत को प्राथमिकता दी और देश के विभिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर और पुणे में अलग-अलग संस्करणों में प्रकाशित किया। शिकायत प्राप्त होने पर, प्रतिवादी की जांच की गई और उसका शपथ बयान दर्ज किया गया। इसके बाद, न्यायिक दंडाधिकारी ने शिकायत का संज्ञान लिया और इसे दर्ज करने और आरोपी को समन जारी करने का निर्देश दिया। नतीजतन, कंपनी (A1) और अपीलकर्ताओं ने अपने खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक याचिका दायर की। दिनांक 18.06.2024 के आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने केवल आरोपी नंबर 1 - बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के संबंध में शिकायत को रद्द कर दिया, और जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए, ये आपराधिक अपीलें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की जाती हैं।

15 यहां शिकायतकर्ता/प्रतिवादी के अनुसार, सभी अभियुक्तों द्वारा मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित मानहानिकारक समाचार लेखों ने पाठकों को शिकायतकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित किया और एक अनुचित और निराधार जनमत को भी बढ़ावा दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए पेश किए गए कार्य नकली हो सकते हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि

दूसरा आरोपी कंपनी का संपादकीय निदेशक (A1) था, जो सामग्री की देखरेख करता था । समाचार पत्रों की और समाचार लेखों के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार था; और अन्य सभी अभियुक्तों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके विभिन्न समाचार पत्रों में विभिन्न समाचार पत्रों में विभिन्न समाचार लेख प्रकाशित किए, ताकि शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर या जनता के अनुमान में उसकी छवि को कम करके उसकी नीलामी की सफलता को बाधित किया जा सके, जिससे आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दंडनीय अपराध किए जा सकें।

16 दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत में लगाए गए आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया। जबकि उन्होंने आमतौर पर तर्क दिया है कि न्यायिक दंडाधिकारी सीआरपीसी की धारा 202 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहे, उनके संबंधित प्रकाशनों के संबंध में विशिष्ट आरोपों के लिए उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं संदर्भ में आसानी के लिए नीचे सारणीबद्ध की गई हैं:

अपीलकर्ता/ आरोपी का नाम	**प्रकाशन का विवरण**	**आरोपों के जवाब**
जयदीप बोस - A2 एस एल पी (सी आर एल) संख्या 10212/2024	कंपनी के संपादकीय निदेशक (A1)	उन्होंने न तो कथित समाचार लेखों का लेखन किया और न ही उनके प्रकाशन से जुड़े थे और इसलिए, उन्हें इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

नर्गिश सुनावाला - A12 एस एल पी (सी आर एल) संख्या 13443/2024	20.07.2014 टाइम्स ऑफ इंडिया	अपीलकर्ता से संबंधित लेख पूरी तरह से मौजूदा सार्वजनिक प्रवचन और अन्य प्रतिष्ठित स्रोतों द्वारा पहले प्रकाशित सामग्री पर आधारित था। प्रतिवादी को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था और लेख का उद्देश्य जनता को महत्वपूर्ण रुचि और चिंता के मामलों के बारे में सूचित करना था। कोई निर्णय या कोई आक्षेप नहीं दिया गया था।
स्वाति देशपांडे A8 एसएलपी (सीआरएल) संख्या 15653/2024 में अपीलकर्ता नंबर 1	28.06.2014 टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई	इसके चेहरे पर लेख, मानहानिकारक नहीं है। लेख के समग्र पढ़ने से पता चलता है कि एक संतुलित दृष्टिकोण लिया गया था क्योंकि यह केवल शिकायतकर्ता सहित सभी संबंधित पक्षों के विचारों को प्रस्तुत करता है। लेख में शिकायतकर्ता को बदनाम करने के किसी भी इरादे या ज्ञान का सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है।
शुब्रो नियोगी एसएलपी (सीआरएल) संख्या	29.06.2014 टाइम्स ऑफ इंडिया, कोलकाता	लेख में कहीं भी शिकायतकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं है, बल्कि कलाकृतियों की प्रामाणिकता की जांच के लिए विशेषज्ञों के एक पैनल

15653/2024 में A9 अपीलकर्ता नंबर 2		के निर्माण के लिए कला विशेषज्ञों द्वारा कॉल पर रिपोर्ट की गई है। शिकायतकर्ता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। जब इसे पूरी तरह से पढ़ा जाता है, तो लेख को मानहानिकारक नहीं माना जा सकता है।
रत्नोत्तम सेनगुप्ता -A10 एसएलपी (सीआरएल) संख्या 15653/2024 में अपीलकर्ता नंबर 3	06.07.2014 टाइम्स ऑफ इंडिया कोलकाता	लेख को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल कलाकृतियों के आसपास के विवाद पर रिपोर्ट करता है और संतुलित तरीके से, शिकायतकर्ता की टिप्पणियों और स्थिति को शामिल करता है, साथ ही कला-क्षेत्र के विभिन्न अन्य विशेषज्ञों के विचारों को भी प्रस्तुत करता है। लेख को संपूर्णता में पढ़ना मानहानि का गठन नहीं करता है।
रश्मि मेनन- एसएलपी (सीआरएल) संख्या 15653/2	27.06.2014 इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली	लेख स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अपीलकर्ता ने केवल कुछ इनपुट दिए थे। भले ही, लेख को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल एमएफ हुसैन प्रतिष्ठान/फाउंडेशन द्वारा शिकायतकर्ता को एक कानूनी विधि-

024 में A13 अपीलकर्ता नंबर 4		सूचना भेजने की रिपोर्ट करता है, साथ ही शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया भी प्रदर्शित करता है, जिसने उस समय व्यक्त किया था कि उसे इस तरह के विधि-सूचना के बारे में पता नहीं था। इस लेख को किसी भी तरह से मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है।
नीलम राज - A4 एसएलपी (सीआरएल) संख्या 16153/ 2024 में अपीलकर्ता	27.06.2014 टाइम्स ऑफ इंडिया, बैंगलोर 27.06.2014 टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली 27.06.2014, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई 27.06.2014 टाइम्स ऑफ इंडिया, पुणे 28.06.20 14	अपीलकर्ता द्वारा लिखे गए समाचार लेखों को पढ़ने को मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है। ये समाचार लेख, पूरी तरह से पढ़े जाते हैं, केवल कला विशेषज्ञों के विचारों पर रिपोर्ट करते हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को नकली कला के बारे में चेतावनी देते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी भी समाचार लेख से यह पता नहीं चलता है कि शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा था।

	टाइम्स ऑफ इंडिया, बैंगलोर	

17 प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने से पहले, प्रत्येक अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत में उठाए गए विशिष्ट आरोपों को देखना आवश्यक है, जो निम्नानुसार निकाले गए हैं:

> *"2. ..... दूसरा आरोपी पहले आरोपी का संपादकीय निदेशक है। तीसरा आरोपी पहले आरोपी का कार्यकारी संपादक है। दूसरा और तीसरा आरोपी समाचार पत्रों की सामग्री की देखरेख करता है और सामग्री के लिए जिम्मेदार है।*
>
> *12. 27.06.2014 को, चौथे आरोपी, **सुश्री नीलम राज** ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, "Fakes at Art Auction Raise Huge Storm".("कला नीलामी में नकली भारी तूफान उठाते हैं")। टाइम्स ऑफ इंडिया, बैंगलोर संस्करण के पहले पन्ने पर ही और इस शीर्षक के ठीक नीचे शिकायतकर्ता का नाम है। यह लेख पृष्ठ 14 पर एक और शीर्षक के साथ जारी है, "Biggest Counterfeit Indian Art Controversy Hits Auction".("सबसे बड़ा नकली भारतीय कला विवाद हिट्स ऑक्शन")। इस शीर्षक के तहत, आगे कहा गया है, "नीलामी घरों में से सबसे सम्मानित घरों में एक या दो प्रतियां सामने*

आई हैं, लेकिन बैंगलोर स्थित बिड एंड हैमर की आगामी नीलामी पर भारतीय कला बाजार में प्रकाश में आने वाला शायद सबसे बड़ा विवाद है। लेख में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के अध्यक्ष से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। शिकायतकर्ता को इस तरह के कॉल कभी नहीं मिले और यह अनैतिक है और तथ्यों को स्पष्ट किए बिना एक लेख प्रकाशित करना गलत है। यह भी दावा किया गया है कि परिवादी 2010 में Souza की एक कृति को लेकर इसी प्रकार के विवाद में "फँसा" था। इसके अतिरिक्त, ऐसी घटनाएँ और कृतियाँ वर्णित की गई हैं जिनका परिवादी से कोई संबंध नहीं है, जिससे पाठक पर यह छाप पड़ती है कि परिवादी इन कृतियों में भी शामिल है और वह नकली कला और पेंटिंग्स का नियमित व्यापार करने वाला (habitual dealer) है।

13. ये आरोप और संकेत स्पष्ट रूप से असत्य और भ्रामक हैं तथा उन कृतियों की अत्यंत नकारात्मक छवि प्रस्तुत करते हैं जिन्हें परिवादी ने विस्तृत अध्ययन और सत्यापन के पश्चात, considerable लागत और प्रत्येक कृति की अत्यंत विश्वसनीय प्रमाणीकरण प्रक्रिया के बावजूद नीलामी में प्रस्तुत किया। इन आरोपों में बर्दवान के महाराजा की पोती, नम्रता शिरोडकर और महेश बाबू और अन्य को भी बदनाम किया गया है।

*14. 27.06.2014 को ही, चौथे आरोपी, **सुश्री नीलम राज** ने टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली, मुंबई और पुणे संस्करणों में पहले पन्ने पर "फेक हिट्स आर्ट ऑक्शन पर विवाद" शीर्षक के तहत इसी तरह के आक्षेप लिखे। उसी संस्करण के 12वें पृष्ठ पर शीर्षक के तहत, "विशेषज्ञों ने नीलामी कला में हस्ताक्षर की तारीखों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया"...*

15. उक्त आरोपी ने नीलामी के अगले दिन, 28.06.2014, एक और मानहानिकारक (defamatory) लेख प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था: "More Fake Trouble for Indian Art Mart"। यह लेख "Fake" शब्द से प्रारंभ होता है और आरोप लगाता है कि यह लेख कला जगत में हलचल जारी रखता है, विशेष रूप से उन कृतियों को लेकर जो परिवादी की नीलामी में प्रदर्शित की गई थीं।

*16. 27.06.2014 को पांचवें आरोपी श्री मौलिक व्यास और तेरहवें आरोपी **रश्मि मेनन ने** इकोनॉमिक टाइम्स में एक लेख का सह-लेखन किया, जिसका शीर्षक था, "Legal Notice Over Fake Hussains" ("नकली हुसैन पर कानूनी विधि-सूचना") जिसमें पहले पृष्ठ भी शामिल था। यह लेख शिकायतकर्ता को उसी दिन जारी किए गए कानूनी विधि-सूचना को संदर्भित करता है जिस दिन विधि-सूचना भेजा गया था और शिकायतकर्ता द्वारा इसे प्राप्त होने से पहले भी।*

इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि लेख का उद्देश्य बदनाम करना था

शिकायतकर्ता, पूरी तरह से जानते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स के पाठकों में प्रमुख उद्योगपति शामिल हैं, जो कला के जाने-माने पारखी हैं और शिकायतकर्ता के संभावित ग्राहक हैं। यह ध्यान रखना उचित है कि उक्त दो आरोपियों ने शिकायतकर्ता पर लगाए गए झूठे आरोपों के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा जारी किए गए खंडन और स्पष्टीकरण को आसानी से नजरअंदाज कर दिया, इसके बावजूद कि यह खंडन उन्हें अगले दिन प्रकाशन के लिए समय पर भेजा गया था। यह वास्तव में शिकायतकर्ता को बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। इसके बाद, तेरहवें अभियुक्त, सुश्री रश्मि मेनन ने शिकायतकर्ता से खंडन प्राप्त होने की पुष्टि की। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने खंडन प्रकाशित क्यों नहीं किया, उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ जवाब देना बंद कर दिया। यह शिकायतकर्ता को बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है।

*18. 13.06.2014 को, आठवीं आरोपी, **सुश्री स्वाति देशपांडे** ने टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई संस्करण में एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था, "Auction House Denies 22 Hussain Works are Fake". "(नीलामी घर ने 22 हुसैन कार्यों को नकली होने से इनकार किया") । लेख कानूनी विधि-सूचना*

और उत्तर के विवरण को संदर्भित करता है, इस प्रकार शिकायतकर्ता के काम पर संदेह पैदा करता है। यह एक ऐसा संकेत है जिसने शिकायतकर्ता की छवि को धूमिल किया है।

19. 29.06.2014 को, नौवें आरोपी ***श्री शुभ्रो नियोगी*** *ने टाइम्स ऑफ इंडिया, कोलकाता संस्करण में एक लेख लिखा था, जिसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा आयोजित नीलामी में नकली थी। नौवें आरोपी की दुर्भावनापूर्ण मंशा इस तथ्य से स्पष्ट रूप से स्थापित होती है कि लेख के समर्थन में प्रकाशित चित्रों को कैटलॉग में भी नहीं दिखाया गया था क्योंकि वे नीलामी का हिस्सा नहीं थे। इसलिए आरोपी को नीलामी में पेंटिंग्स के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उन्हें नकली कहने का बीड़ा उठाया। इस आरोप ने शिकायतकर्ता की छवि को धूमिल किया है।*

20. 06.07.2014 को दसवां अभियुक्त। ***श्री रत्ननाथ सेनगुप्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया,*** *कोलकाता संस्करण में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था ("Who Speaks the Last Word on*

Fakes".)"कौन नकली पर अंतिम शब्द बोलता है"। लेख विशेष रूप से इस बात पर जोर देता है कि शिकायतकर्ता द्वारा आयोजित नीलामी के लॉट 82 और 83 की पहचान की गई थी

नकली के रूप में। इस आरोप ने शिकायतकर्ता की छवि को धूमिल किया है।

22. 20.07.2014, बारहवें अभियुक्त, ***सुश्री नरगिस सुनावाला ने टाइम्स ऑफ इंडिया,*** *बैंगलोर संस्करण में एक लेख लिखा, जिसमें यह संकेत दिया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा नीलाम किए गए कार्यों में उचित प्रामाणिकता प्रमाण पत्र नहीं हैं, जो जानबूझकर शिकायतकर्ता की नीलामी में शामिल महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को दबा दिया गया है, जो सार्वजनिक डोमेन में था। इस आरोप ने शिकायतकर्ता की छवि को धूमिल किया है।*

18 यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता (A2) जयदीप बोस कंपनी के संपादकीय निदेशक हैं और अन्य अपीलकर्ता विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कथित मानहानिकारक समाचार लेखों के लेखक हैं। प्रतिवादी ने मानहानि का अपराध करने के लिए आरोपी के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की।

19 आइए पहले हम अपीलकर्ता (A2) जयदीप बोस के मामले से निपटें, जो अन्य अभियुक्तों से अलग पायदान पर खड़े हैं। वह कंपनी के संपादकीय निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो संबंधित सभी समाचार पत्रों का मालिक है। उनके अनुसार, वह न तो लेखक हैं और न ही विचाराधीन समाचार लेखों के संपादक हैं और उनकी भूमिका केवल प्रशासनिक प्रकृति की है, प्रकाशन प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि समन जारी करने की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक अनियमितता थी क्योंकि वह मुंबई में रहते हैं, जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है,

और इसलिए, न्यायिक दंडाधिकारी को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत अनिवार्य गवाहों से पूछताछ करके जांच करने की आवश्यकता थी।

19.1 जैसा कि पहले ही दोहराया गया है, यह संपादक है जो प्रकाशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेता है कि प्रकाशित सामग्री मानहानि के आसपास के कानूनों सहित कानूनी मानकों का पालन करती है। यह अच्छी तरह से तय है कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 ("अधिनियम") एक संपादक पर उच्च स्तर की जिम्मेदारी और दायित्व लगाता है। अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि प्रत्येक समाचार पत्र या आवधिक प्रकाशन को संपादक और मालिक का नाम निर्दिष्ट करना होगा। धारा 7 एक खंडन योग्य धारणा बनाती है कि जिस संपादक का नाम समाचार पत्र में छपा है, उसे उस प्रकाशन के संबंध में किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में संपादक माना जाएगा। चूंकि एक "संपादक" को परिभाषित किया गया है । एक समाचार पत्र में प्रकाशित मामले के चयन को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति के रूप में, यह अनुमान इस हद तक जाता है कि वह वह व्यक्ति था, जिसने अखबार में प्रकाशित मामले के चयन को नियंत्रित किया था। हालांकि, केवल इसलिए कि अधिनियम कंपनी के प्रकाशन में अन्य भूमिकाएं रखने वाले व्यक्तियों का उल्लेख नहीं करता है, जैसे कि संपादकीय निदेशक, या उनके नाम के प्रकाशन को अनिवार्य नहीं करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों को किसी भी मानहानिकारक सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता

है। मुख्य अंतर यह है कि एक संपादक के विपरीत, जिसके खिलाफ एक वैधानिक अनुमान लगाया जाता है, शुरुआत में संपादकीय निदेशक के खिलाफ ऐसी कोई धारणा नहीं है [देखें: केएम मैथ्यू बनाम केए अब्राहम]।

19.2 शिकायत की ओर मुड़ते हुए, जो इसमें भी आवश्यक है, प्रकाशन प्रक्रिया में आरोपी की भूमिका के संबंध में विशिष्ट आरोप हैं। इस न्यायालय ने गंभीरसिंह आर. डेकरे बनाम फाल्गुनभाई चिमनभाई पटेल में कहा कि जबकि अधिनियम किसी अन्य कानूनी इकाई को मान्यता नहीं देता है। मुख्य संपादक, प्रबंध संपादक आदि के खिलाफ एक अनुमान लगाने के लिए, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन केवल तभी जब उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए जाते हैं। वर्तमान मामले में, शिकायत में केवल यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता (A2) ने प्रकाशनों की देखरेख की। यह स्थापित करने के लिए कोई अन्य कथन नहीं किया गया था कि अपीलकर्ता (A2) समाचार पत्रों के प्रकाशनों की सामग्री के चयन को नियंत्रित करने के लिए कैसे जिम्मेदार था। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, वह कंपनी के संपादकीय निदेशक हैं, न कि व्यक्तिगत समाचार पत्रों के। इस प्रकार, हमारे विचार में, विशिष्ट या ठोस विवरण के बिना इस तरह का एक व्यापक, सामान्य या व्यापक बयान समन जारी करने को उचित नहीं ठहरा सकता है।

19.3 न्यायिक दंडाधिकारी , उचित जांच और पूछताछ के बिना, अपीलकर्ता (A2) को समन जारी करने के लिए आगे बढ़े। यहां यह भी ध्यान रखना उचित है कि अपीलकर्ता (A2) मुंबई में रहता है, जो संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसे परिदृश्य में, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, न्यायिक दंडाधिकारी को शिकायत के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। धारा 202(1) सीआरपीसी के अनुसार। तथापि, वर्तमान मामले में ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी। इसलिए, इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि अपीलकर्ता (A2) के खिलाफ शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं है।

20. अन्य अपीलों में अपीलकर्ताओं के संबंध में, प्राथमिक न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेशों से यह स्पष्ट है कि विभिन्न अभियुक्तों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखे गए सभी समाचार लेखों पर विचार नहीं किया गया था। आक्षेपित आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने सुश्री नीलम राज (A4) द्वारा लिखित केवल एक लेख का उल्लेख किया और न तो शेष अभियुक्तों द्वारा लिखे गए अन्य समाचार लेखों पर ध्यान दिया और न ही चर्चा की। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 202 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया गया था। अपीलकर्ता अर्थात्, A8, A9, A10, A12 और A13 मुंबई/कोलकाता में रहते हैं, जबकि शिकायत बैंगलोर में दायर की गई थी। शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने के लिए कोई गवाह पेश करने में विफल रहा कि कथित आरोपों ने दूसरों के अनुमान में उनकी प्रतिष्ठा को कम कर दिया था और न्यायिक दंडाधिकारी , केवल शिकायतकर्ता के बयान

की समीक्षा करने के बाद, समन जारी करने के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार, न्यायिक दंडाधिकारी का आदेश स्पष्ट रूप से प्रक्रियात्मक अनियमितता से ग्रस्त है। आमतौर पर, इस तरह की अनियमितताओं के लिए रिमांड की आवश्यकता होगी। तथापि, वर्तमान मामले में नीलामी दिनांक 27-06-2014 को की गई थी और शिकायत दिनांक 22-08-2014 को दर्ज की गई थी। हमारे सामने ऐसी कोई सामग्री भी नहीं रखी गई है जिससे यह पता चले कि समाचार पत्रों में प्रकाशित कथित समाचार लेखों के कारण नीलामी असफल रही या वास्तव में कोई क्षति या हानि हुई थी। इसके बावजूद, इस स्तर पर, समन जारी करने से पहले गवाहों की नए सिरे से जांच के लिए मामले को रिमांड पर लेने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि गवाहों को सुरक्षित करने की संभावना कम है। यह केवल मुकदमेबाजी को लम्बा खींचेगा, विशेष रूप से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि नीलामी पहले ही समाप्त हो चुकी है और एक दशक से अधिक समय बीत चुका है। हम अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों पर भी ध्यान देते हैं कि शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को बदनाम करने या नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। विशेष रूप से, इस न्यायालय ने दिनांक 20.07.2022 के सामान्य आदेश के माध्यम से 'मेसर्स डीएजी प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स बिड एंड हैमर ऑक्शनियर्स (पी) लिमिटेड' ने उसी शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत से उत्पन्न होने वाले संख्या 1008/2022 आदि मामलों वाली इसी तरह की आपराधिक अपीलों की अनुमति दी। उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा समन जारी करने को रद्द करने

के इच्छुक हैं। नतीजतन, अपीलकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही भी रद्द की जा सकती है।

21. अलग होने से पहले, हम इस बात पर जोर देना आवश्यक समझते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (A) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है। साथ ही, यह दोहराया जाता है कि मीडिया में काम करने वालों, विशेष रूप से, प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्तियों, लेखकों आदि को किसी भी बयान, समाचार या राय को प्रकाशित करने से पहले अत्यधिक सावधानी और जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। जनमत को आकार देने में मीडिया की शक्ति महत्वपूर्ण है और प्रेस के पास उल्लेखनीय गति के साथ सार्वजनिक भावनाओं को प्रभावित करने और धारणाओं को बदलने की क्षमता है। जैसा कि बुलवर लिटन ने उपयुक्त रूप से कहा है, “The Pen is mightier than the sword”. "कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है"। इसकी विशाल पहुंच को देखते हुए, एक भी लेख या प्रतिवेदन लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित हो सकती है, उनके विश्वासों और निर्णयों को आकार दे सकती है, और इसमें संबंधित लोगों की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, जिसके परिणाम दूरगामी और स्थायी हो सकते हैं। यह मीडिया रिपोर्टिंग में सटीकता और निष्पक्षता की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, खासकर जब व्यक्तियों या संस्थानों की अखंडता को प्रभावित करने की क्षमता वाले मामलों से निपटते हैं। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, समाचार लेखों का प्रकाशन जनहित में और अच्छे विश्वास के साथ किया जाना चाहिए।

22. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, हम इन सभी अपीलों की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश और समन आदेशों के साथ-साथ प्रतिवादी द्वारा दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करते हैं, जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, यदि कोई लंबित आवेदन हो, तो वह भी निस्तारित (निपटाया) माना जाएगा।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दि गयी।

शीर्ष टिप्पणियाँ निधि जैन द्वारा तैयार की गई।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
मधु कुमारी के द्वारा *किया गया है।*